It is, therefore, requested that the Government of India should start a much more successful and effective all-round mission to save the wild life in the country. Thank you.

To develop National Highways in Orissa

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे विशेष उल्लेख का विषय है- उड़ीसा के राजमार्गों के विकास हेतु मांग।

महोदय, सन् 2000 से उड़ीसा उद्योग की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। पहले मुख्यतया यह एक कृषि आधारित प्रांच था, लेकिन आज पब्लिक सैक्टर के साथ-साथ विदेशी पूंजी निवेशक भी प्रदेश में काफी मात्रा में आ रहे हैं। अपने देश के घरेलू निवेशकों ने भी वहां उद्योग बैठाना चालू कर दिया है। इसका एक मुख्य कारण है कि इस प्रदेश की जनता बहुत शांतिप्रिय है। मात्र इस व्यापक औद्योगिकीकरण के कारण अगर उन्हें यातायात हेतु राजपथ, ग्रामपथ यानी कि रोड-रास्ता भी न मिले, तो यह कितने दिन तक सहनीय होगा।

महोदय, 1998 से पहले तो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नाममात्र का ही था, उसके बाद धीरे धीरे कई मार्गों को राजमार्ग का दर्जा दिया गया, प्रशस्तीकरण तथा विकास के लिए कुछ पैसा दिया गया, लेकिन अब शायद वह कार्य प्रायः ठप हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215, जो कि याजपुर जिले के पाणिकीइलि से सुंदरगढ़ जिले के राजामुंडा तक व्याप्त है, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23, जो कि अनुगुल जिले के बंअरपाल से राउरकेला होता हुआ झारखंड प्रदेश में रांची तक गया है, इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत भी अत्यंत खराब है। ककित दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल कोयला तथा ऑयरन-ओर के परिवहन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 की हालत भी अत्यंत खराब है। इन तीन राष्ट्रीय राजमार्गों के द्रुत विकास हेतु मैं सरकार के सामने पुरजोर मांग रखता हूं, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 के भुवन-कामारण्यानगर खंड के प्रति तुरंत ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42, जो कि सांस्कृतिक राजधानी कटक और पश्चिमी उड़ीसा के प्रमुख शहर संबलपुर को जोड़ता है, का भी 4 लेनिंग का काम प्रारम्भ किया जाना चाहिएं। इसी मार्ग पर हाल के दो साल में ऐक्सिडेंट्स में दो विधायकों की जान गई है। इसी राजमार्ग पर पड़ने वाले अनुगुल शहर के लिए बाइपास की भी व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए।छ राजमार्गों की बदहाली से जनता बहुत परेशान है, अतःयुद्धस्तर पर इनकी मरम्मत, विकास, 4 लेनिंग, बाइपास निर्माण आदि कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर निवेशकों से भी वार्ता की जानी चाहिए।

कैसे भी हो, राज्य के राजमार्गों का तुरंत विकास किए जाने हेतु मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के सामने दृढ़ दावा करता हूं।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): सर, मैं पाणि जी की रवानी का समर्थन करता हूं।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی ''مدھیہ پردیش'' : سر، میں پانی جی کی روانی کا سمرتھن کرتا ہوں-

उपसभाध्यक्ष (**श्री दिनेश त्रिवेदी**): श्री तरलोचन सिंह। Not present.

Demand to keep vigilance on the Indo-Pak Border

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मेरा विशेष उल्लेख पश्चिमी सीमा पर पाक की सामरिक तैयारी से संबंधित है।

महोदय, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की धुन में व्यावहरिक स्थितियों और व्यापक देशहित को ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान की जमीन पर अब भी पशिक्षण केन्द्र बाकायदा काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने राजस्थान से लगती अपनी सीमा से सामरिक ताकत को मजबूत करने का जोरदार प्रयास किया है-जहां बीकानेर-जैसलमेर से लगती सीमा के निकट करीब 150 से ज्यादा बंकरों का (उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन) पीठासीन हुए) निर्माण किया है, वही इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट 24 से ज्यादा नई सीमा चौकियों का निर्माण भी किया है। पाकिस्तान द्वारा एक तरफ संबंध सुधारने की पहल और दूसरी तरफ लगातार किये जा रहे सामारिक निर्माण भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। समय-समय पर पाकिस्तानी समारिक कवायद की खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती जा रही हैं। इसलिए संबंध सुधारने की धुन में देश की सुरक्षा का भी हर वक्त ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही आशंका व्यक्त की है। अत:मैं मांग करता हूं कि सरकार उक्त संबंध में पूरी तरह से चौकस रहे। धन्यवाद।

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान): मैं इनको ऐसोसिएट करता हूं।

Need to offer incentives to some districts of Andhra Pradesh

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY (Andhra Pradesh): Sir, the Government of India started offering a package of attracting incentives, comprising both fiscal and non-fiscal measures for attracting industrial investment in Uttaranchal, Himachai Pradesh, Jamrnu and Kashmir and North-Eastern States. These incentives include exemption of Central Excise, waiving of State tax, that is, total exemption from

t[ ] Transliteration in Urdu Script.